भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †4038

दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

दुर्लभ मृदा खनिजों के लिए भारत की आयात पर निर्भरता

†4038. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले दुर्लभ मृदा खनिजों और मैगनेट के लिए चीन पर निर्भर है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीन द्वारा आपूर्ति और अधिक कड़े किए जाने की स्थिति में भारत का मौजूदा स्टॉक कितने समय तक रहेगा;
(ख) घरेलू खनन और दुर्लभ मृदा खनिजों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं के अंतर्गत अब तक जारी की गई निधि कितनी है और आरंभ की गई परियोजनाओं सहित की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या अन्य देशों से दुर्लभ मृदा खनिजों की प्राप्ति हेतु भारत के प्रयासों के परिणाम प्राप्त होने लगे हैं और यह चीन से अभी भी आयात की जा रही मात्रा की तुलना में कितना है; और
(घ) सरकार की इस तरह के एक संवेदनशील संसाधन के लिए किसी एक देश पर निर्भरता को कम करने हेतु दीर्घकालिक योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) से (घ): वित्त वर्ष 2025-26 में, भारत द्वारा दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के कुल आयात का 30% से अधिक चीन से किया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 में, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के अधीन आईआरईएल (भारत) लिमिटेड ने दुर्लभ मृदा यौगिक का 5.47 किलो टन उत्पादन होने की सूचना दी है।

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक घटक इकाई है, जो देश की तटीय/अंतर्देशीय/रिवराइन प्लेसर रेत में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) की खोज करती है, जिसमें मोनाज़ाइट जैसे दुर्लभ मृदा खनिज शामिल हैं। अब तक, एएमडी ने आरईई के अनुमानित संसाधन की इस प्रकार पुष्टि की है:

- आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में समुद्री तटों, टेरी, बीच सैंड और अंतर्देशीय जलोढ़ में पाए जाने वाले 13.30 मिलियन टन (एमटी) मोनाजाइट संसाधन में लगभग 7.31 मिलियन टन (एमटी) स्व-स्थाने कुल दुर्लभ मृदा ऑक्साइड समतुल्य (टीआरईओ सम.) मौजूद है।

- गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कठोर चट्टानी क्षेत्रों में 1.30 मिलियन टन स्व-स्थाने आरईई संसाधन (टीआरईओ सम.)

इसके अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने पूरे भारत में कठोर चट्टानों में आरईई संसाधनों का भी अनुमान लगाया है।

इसके अलावा, क्षमताओं को सुदृढ़ करने, आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने, घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i) महत्वपूर्ण खनिजों (आरईई सहित) की दीर्घ-कालिक सतत आपूर्ति को सुनिश्चित करने और खनिज गवेषण और खनन से लेकर खनिज संवर्धन, प्रसंस्करण और एंड-ऑफ-लाइफ उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को अनुमोदन।

ii) एनसीएमएम आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए निवेश में सहायता प्रदान करने की संकल्पना करता है। तदनुसार, विदेशी क्षेत्राधिकारों में खनिज गवेषण करने के लिए भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, खान मंत्रालय ने 16 जुलाई 2026 को "विदेशी खनिज गवेषण संवर्धन दिशानिर्देश" परिचालित किए हैं।

iii) इसके अलावा, एनसीएमएम के तहत, देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू प्रसंस्करण को सुदृढ़ करने और स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा

अवसंरचना का उपयोग करके खनिज प्रसंस्करण पार्कों को विकसित करके घरेलू महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमताओं को सहायता प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

iv) इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट में खनिज-संपन्न राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ मृदा कॉरिडोर्स की स्थापना करने के लिए सहायता की घोषणा की गई है।

v) खान मंत्रालय ने 15 ब्लॉकों जिसमें समुद्री रेत खनिजों [(आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसी)-10, आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड-4)] और कठोर चट्टानों में आरईई निक्षेप के एक ब्लॉक के लिए गुजरात खनिज विकास निगम, गुजरात को पूर्व स्वीकृति प्रदान की है।

vi) भारत दुर्लभ मृदा तत्वों सहित महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से संसाधन-संपन्न देशों के साथ भी जुड़ा हुआ है।

*****